परिवार ऋण योजना का विस्तार करके कार्यक्रम हेतु आधारभूत ढांचा सहायता को मजबूत बनाने आदि जैसे उपायों की मार्फत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ करके गरीबी में कमी लाने के प्रयासों में वृद्धि की है ।

कापार्ट द्वारा रोजगार पैदा करने हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन

768. **श्री आस मोम्हमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कापार्ट" ने ग्रामीण जनता के लिए रोजगार पैदा करने के लिए किसी योजना को कार्यान्वित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान "कापार्ट" द्वारा पैदा किए गए रोजगार के अवसरों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने ग्रामीण लोगों को इनसे लाभ हुआ है ;

(ङ) आठवीं योजनावधि के दौरान इससे कितने लोगों को लाभ होने की संभावना है;

(च) उक्त योजना के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(छ) शेष धनराशि का उपयोग करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) कापार्ट स्वैच्छिक एजेन्सियों की मार्फत जवाहर रोजगार योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों को अतिरिक्त लाभदायक रोजगार सृजित करना है ।

(ग) व (घ) कापार्ट द्वारा कार्यान्वित की जा रही जवाहर रोजगार योजना की परियोजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 77.74 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजित किया गया है ।

(ङ) आठवीं योजना अवधि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(च) व (छ) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कापार्ट को निधियां स्वयं सेवी एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के अनुसार आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष रिलीज की जाती है । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कापार्ट को पिछले तीन वर्षों के दौरान 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कापार्ट ने इस अवधि के दौरान उपलब्ध आदि शेष सहित 26.53 करोड रुपये का उपयोग किया गया है ।

मध्य प्रदेश के शहरों के लिए जल आपूर्ति योजना

769. **श्री राघवजी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 20,000 लोगों से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए जल आपूर्ति योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो वे शहर कौन-कौन से हैं, जिनके लिए योजनाएं भेजी गई हैं। क्या इनकी लागत कितनी-कितनी है और कौन-कौन सी तिथियों को ये योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गई थीं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब होने के क्या-क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)	प्राप्ति की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	बादानगर मे जल-सप्लाई की संवर्द्धन योजना . .	232.00	4–4–94	सी.पी.एच. ई. ई. ओ. की जांच के तहत
2.	दीवास जल-सप्लाई योजना (संशोधित) . .	5155.00	6–4–94	सी. पी. एच. ई. ई. ओ. की जांच के तहत
3.	शामगढ़ व गारोध कस्बों और 29 सूखाग्रस्त गांवों की समूह जल-सप्लाई योजना .	1338.00	6–4–94	राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गयी थी जिनका उत्तर दिसम्बर, 1994 में प्राप्त हुआ, जो योजना सी. पी. एच. ई. ई० ओ. की जांच के तहत है।
4.	बायोरा नगर में अन्तरिम जल-सप्लाई योजना चरण-2	167.00	5–1–95	सी. पी. एच. ई. ई. ओ. की जांच के तहत
5.	जामाई वृद्धि जल सप्लाई योजना	168.00	13–2–95	सी. पी. एच. ई. ई. ओ. की जांच के तहत।

सी. पी. एच. ई. ई. ओ. :— केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन

नल जल योजना का कार्यान्वयन

770. **श्री राघवजी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार नल जल योजना केवल उन्ही गांवों में कार्यान्वित होती है, जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के आधार पर 2000 लोगों से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब 1981 जनगणना के स्थान पर 1991 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा तथा क्या इस संबंध में निर्धारित जनसंख्या के मानदंड को 2000 से घटाकर 1000 व्यक्ति कर दिया जाएगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) मध्य प्रदेश के विदिशा तथा रायसेन जिलों के उन गांवों के नाम क्या हैं, जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के आधार पर 2000 व्यक्तियों मे अधिक थी, किन्तु वहां नल जल योजना कार्यान्वित नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं ?